(d) Based on documented latest figures (.1992-93) expenditure on Agricultural Research, Education and Extension Education by ICAR/DARE, it is 0.186 per cent. This does not include expenditure by the State Government on the State Agricultural Universities and other research units operated by them. Since agriculture is a State subject, such expenditures are quite significant.

Schemes by U.P. Agricultural Development

4893. SHRI SANJAY DALMIA:

MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the State Government of Uttar Pradesh have suubmited some schemes relating to agricultural develop ments to the Central Government for approval;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the decision taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAlM): (a) to (c) The Government of Uttar Pradesh has submitted a proposal for inclusion of a project. Uttar Pradesh Diversified Agriculture Support Project for World Bank Assistance. The Government of Uttar Pradesh is already engaged in conducting studies for different components under this Projet. The project preparation is still in the initial stages.

The Government of Uttar Pradesh has also forvvardtd a project proposal for Training and Extension of Women in Agriculture to be funded by the Govern ment of Netherlands. The Project has been returned to U.P. Government for certain clarifications.

;

"गोपाल योजना" का कार्यान्वयन

4894. चौधरी हरमोहन सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या-क्या हैं जहां पशुधन की नस्ल के समेकित विकास हेतु "गोपाल योजना" को लागू किया जा रहा है ;

(ख) उपर्युक्त योजना के अंतर्गत किए गए उपायों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उपर्युक्त योजना को लागू करने के लिए राज्य-वार कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) "गोपाल योजना" के नाम से कोई योजना नहीं है। तथापि, वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना को क्रियान्वित करने वाले राज्यों को, चुनिन्दा पनधारा के प्रत्येक गांव में जो परियोजना के पशुधन विकास घटक से भी सहयोजित है, एक भूमिहीन सम्पर्क किसान को "गोपाल" नाम से पदनामित किए जाने की आवश्यकता है । उन राज्यों के नाम जो वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना को क्रियान्वित कर रहे हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं । (नीचे देखिए) ।